पार्किंग में ही मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा

सुविधा देने के लिए ईवी मैन्युफैक्चरिंग नीति में होगा संशोधन

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति में संशोधन करने जा रही है। प्रस्तावित संशोधन में वाहनों को पार्किंग में ही चार्जिंग समेत कई सुविधाएं देने का प्रावधान करने की तैयारी है। चंडीगढ़ और मुंबई में ई-वाहनों को पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा पहले से है। अब नगर विकास विभाग नोएडा को छोड़कर 9 शहरों के लिए योजना तैयार करा रहा है।

दरअसल, प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है।

नगर विकास विभाग नौ शहरों के लिए बना रहा योजना

हालांकि सुविधा देने के एवज में शुल्क भी लिया जाएगा। पिछले दिनों हुई बैठक में पुरानी नीति में संशोधन कर नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति बनी थी।

इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ही इसे बनाने के लिए जरूरी सुविधाएं देने की भी व्यवस्था पर भी फोकस किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सबसे जरूरी सुविधा चार्जिंग की है जो अभी बहुत बेहतर नहीं है। तय किया गया है कि पार्किंग के अलावा घरों और व्यावसायिक भवनों के आसपास भी चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा।

शहरों के लिए प्लान तैयार करेगा नगर विकास विभाग

सार्वजनिक पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए नगर विकास विभाग को योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें लखनऊ के अलावा कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा और मेरठ शामिल हैं। नोएडा के लिए औद्योगिक विकास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है।

अभी चंडीगढ़ व मुंबई में है व्यवस्था

अभी पार्किंग स्थलों पर चार्जिंग की व्यवस्था सिर्फ चंडीगढ़ और मुंबई जैसे शहरों में ही है। ईवी चार्जिंग नेटवर्क कंपनी ने भी एक बड़े होटल के साथ करार किया है कि वह सभी शहरों में उस समूह के सभी होटलों में भी ई-चर्जिंग स्टेशन लगाने का काम करेगा।